[Shri Syed Nizam-ud-Din]

your seat. Your can discuss it with the Chairman in his chamber. Now please take your seat.

श्री शिव चन्द्र झा : यह आप एक कन्सिसटेंट न्यायपूर्ण नीति अख्तियार करें। यह डबल स्टेंडर्ड सदन के लिए ठीक नहीं होता है।

REFERENCE TO THE SERIOUS FLOOD SITUATION IN EASTERN UTTAR PRADESH

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ध्यान बाढ़ पीड़ित लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप देखें कि तीन अखबारों में–यह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि क्या स्थिति देश की है। आपने जब बाढ़ पीड़ितों के संबंध में चर्चा की––करीब बीस रोज पहले मैंने यह जिक्र किया था कि हम उस इलाके के रहने वाले हैं, हम लोग उस इलाके से आये हैं जहां पर कि बाढ़ के दिनों में वहां का दृश्य समुद्र के टापू जैसा बन जाता है। और भूतपूर्व सरकार ने जो तीस वर्ष या पच्चीस वर्ष कहिए, जो नीतियां बनाईं, उनका परिणाम है कि आज तक कोई सलूशन नहीं निकल सका। जब बाढ़ आती है, जब कोई महामारी होती है तब उस वक्त चर्चा होती है। आपने भी जिक्र किया और मैं भी जिक्र कर रहा हूं। यह क्या ऐसी बात है कि सरकार कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाती कि समस्या का हल हमेशा के लिये निकल जाए।

तो, श्रीमन् मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। आप देखें कि स्थिति क्या है––"बलिया में तुर्ती पार श्रीनगर बांध में गंगा के निरन्तर कटाव की सूचना मिली है। एक समाचार के अनुसार इस बांध में 70 किलोमीटर से लेकर 77 किलोमीटर तक कई तटवर्ती तटबंधों को क्षति पहुंची है। सुरक्षा के लिए चांदपुर से बड़े बड़े पत्थरों को क्षतिग्रस्त स्थानों पर भेजा गया है।"

दूसरे बलिया से मिली खबरों के अनुसार गंगा व घाघरा की बाढ़ से बिहार सीमा के निकट स्थित दोआब क्षेत्र के कई गांव पानी से घिरे हुए है। इन गांवों के लोग बाढ़ से बचने के लिए पेड़ों पर आश्रय लिये हुए हैं।

यह स्थिति यहां पर है, लेकिन सरकार चुप्पी मारे बैठी है, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिल्ली में बैठे हुए है। इसी स्थिति को देखिये कि वहां पर पेड़ों पर लोग अभी भी मौजूद हैं। कल बलिया से लोग आए। वे बता र है कि वहां कोई ऐसे जीवन साधन नहीं हैं। हमारे *मंत्री महोदय कह कर चले गये कि वहां हर जगह* सामान पहुंचा रहे हैं। सो बाढ़ की ऐसी स्थिति है और इससे बढ़ कर पानी जयप्रकाश नगर में है जहां जयप्रकाश जी का घर है।

एक माननीय सदस्य : अच्छा हुआ पाप धुल रहा है।

श्री रामेश्वर सिंह : आपने जो पाप किये हैं उसका परिणाम हम लोग आज भोग र हैं। बलिया जिले में जयप्रकाश नारायण का जन्म-गांव जयप्रकाश नगर गंगा और घाघरा की बाढ़ से जलमग्न हो गया है। पूरा क्षेत्र समुद्र का आभास देता है। जहां तक नजर जाती है, पानी ही पानी। समुद्र में दूर-दराज टापू दीख भी जाते हैं, मगर इस क्षेत्र में ऐसा कोई टापू दृष्टिगोचर नहीं होता।

यह स्थिति बलिया जिले की है। इसकी मैं इसलिये चर्चा करना चाहता हूं कि बलिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह छोर है जहां पर घाघरा और गंगा के बीच में वह जिला बसा हुआ है, उसका पूर्वी किनारा है जहां से एक मील दूर घाघरा नदी और डेढ़ मील दूर गंगा नदी है और जब दोनों का पानी ऊपर आ जाता है तो सारे का सारा जिला, करीब दस लाख की आबादी सारी पानी में डूब जाती है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यह सरकार तुरन्त कार्यवाही करे। भाई साहब ने कहा कि पाप धुल रहा है। मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि

भूतपूर्व सरकार ने कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों को ऊंचा उठाया, पूंजीपतियों को ऊंचा उठाया, संजय गांधी को ऊंचा उठाया, चोर-बाजारी को ऊंचा उठाया, भ्रष्टाचार और गुण्डापरस्ती को ऊंचा उठाया, मगर गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया, सिंचाई की व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया।

श्रीमन्, अगर यह बड़े-बड़े लोगों को सहायता नही देती.... *(Interruptions)* श्रीमन्, भूतपूर्व सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये थी कि गांव की जनता कैसे तरक्की करे, *गांव के लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे।* मगर, भूतपूर्व सरकार ने ऐसा नहीं किया।

मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं और चाहता हूं कि अविलम्ब वहां पर कुछ व्यवस्था हो। यह सरकार तीस वर्ष के कोढ़ को आज ही खत्म नहीं कर सकती। भूतपूर्व सरकार की देन है। आज भी हम उसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। मगर इस सरकार से उम्मीद करते हैं और कहना चाहते हैं कि वह सरकार एक सैन्ट्रल, केन्द्रीय नीति गंगा एरिया, बाढ़-पीड़ित एरिया के लिये बनाये और अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को ले कि जो लोग गंगा, घाघरा एरिया, जो नदी के किनारे बसे हैं उनकी प्रोविन्शल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी न छोड़ कर सारी रिसपान्सिबिलिटी केन्द्रीय सरकार अपने कन्धे पर ले। सारी रिस्पांसिबिलिटी केन्द्रीय सरकार अपने कंध पर लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाए और उस नीति के मातहत दोनों किनारों पर, नदियों के ऊपर तटबंध कायम किए जाएंगे। वह बंध का भी काम करेगा, सड़क का भी काम करेगा।

(Time bell rings.)

2 मिनट दे दीजिए। बलिया में श्रीमन्, अभी जो बंध है उसमें करीब करीब 80–85 लाख रु० खर्च किया गया लेकिन आज झझवा गांव जो जयप्रकाश नारायण जी के गांव से सात-आठ मील दूर है वह गंगा और घाघरा की बाढ़ से जलमग्न हो गया है। सारा बलिया जिला कट कर दक्षिण की तरफ जा रहा है और उत्तर की तरफ घाघरा कट कर के बलिया जिले को काटता जा रहा है। सारे लोगों के घर टूट टूट कर गिर गए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक कारुणिक दृश्य मैं वहां का उपस्थित करना चाहता हूं—माननीय पंडित कमलापति जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं—मैं बताना चाहता हूं वहां पर हमारी क्या स्थिति है। हम लोग आषाढ़ के महीने में मक्का, कोंदू और खरीफ की फसल बोते हैं। आषाढ़ में फसल बोते हैं और एक-दो महीने के बाद गंगा और घाघरा का पानी बहा ले जाता है। बीज भी चला जाता है, सारा परिश्रम भी बेकार हो जाता है और हम को क्या मिलता है? पानी मिलता है। जब हम लोग कार्तिक के महीने में खेती करने जाते हैं, रबी की खेती करने जाते हैं, पानी इतना इकट्ठा होता है कि हम कार्तिक की भी खेती नहीं कर पाते हैं। न तो भूतपूर्व सरकार ने हमारे लिए कोई ध्यान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं बलिया जिला हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में सबसे आगे जिला है जिसने अंग्रेजी सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। स्वर्गीय चीतू पांडे 1942 के वह सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर कब्जा किया था और बैरिया थाना, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं जयप्रकाश नगर की बात कर रहा हूं... *(Time bell rings.)* श्रीमन्, एक मिनट लूंगा। वही इलाका है जहां हंसते हुऐ 21 नौजवान शहीद हो गए और उन्होंने थाने पर कब्जा कर लिया। मैं उस इलाके की बात करता हूं, बलिया जिले की, जहां की देन है आजादी जो देश को मिली है। मगर हम लोग, जो बलिया के लोग है, आज तक उस आजादी को नहीं समझ पाए हैं कि हमको उसका क्या फल मिला। जो अंग्रेजों के राज में हालत थी उस से बदतर हालत कांग्रेस के राज में हुई। मगर जनता पार्टी की सरकार से हमें आशाएं हैं कि वह हमारे लिए कुछ करेगी। श्रीमन्, मैं जनता सरकार से दो बातें चाहता हूं। एक तो तत्काल वहां पर भोजन की व्यवस्था का प्रबंध कराया जाए, गल्ला, राशन और

[श्री रामेश्वर सिंह]

दाल वहां भेजी जाए, लकड़ी भेजी जाए क्योंकि वहां जलाने के लिए कुछ नहीं है, मवेशियों के लिए कोई चारा नहीं है, चारा भेजा जाए। फीस माफ कर दी जाए, दवाएं तुरंत भेजी जाएं। श्रीमन्, करीब 300 लोग मर गए हैं, यह रिपोर्ट अखबार में आई है। मेरा कहना है, मरे हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा दीजिए, उन के बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कीजिए, मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम कीजिए, लोगों के लिए नौकरी का इंतजाम कीजिए और सरकारी वसूलियां माफ कर दी जाएं। श्रीमन्, मैं सही बात आप से बताऊं तो सत्तू वहां के लोगों को नहीं मिल पाता है-- जो यहां पर हरिजनों की वकालत करते है, रामानन्द यादव जी से कहना चाहता हूं-- वहां केवल एक सेर सत्तू हरिजनों को दिया जाता है। आप को शरम नहीं आती है, आप किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से अपना चेहरा दिखाते है जब कि 30 वर्ष के कांग्रेस राज में हिन्दुस्तान की जनता के लिए भोजन का इंतजाम नहीं किया, दवा का, कपड़े का, रहने का इंतजाम नहीं किया? अभी देखिए, आगे आगे क्या होता है। हमारे ऐसे ऐसे आदमी चुन कर आएंगे जो आपकी नाक में नकेल देंगे और इन्दिरा गांधी को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे। वह पापिन है जिसने बलिया जिले की जनता को ठुकराया है, जिसके कारण आज जयप्रकाश नारायण मरण शैया पर हैं। आज अगर वे सही हालत में होते तो देखते क्या कर दिखाते। मगर जयप्रकाश नारायण को उस सरकार ने, रामानन्द यादव की सरकार ने मरण शैया में डाल दिया है....

(Time bell rings.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED NIZAM-UD-DIN) : Please take your seat.

श्री रामेश्वर सिंह : मैं समाप्त करता हूं मगर इतना कहना चाहता हूं, आप पुनरावृत्ति मत करिए, उन गलतियों के रास्ते में मत चलिए। *(Time bell rings.)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED NIZAM-UD-DIN) : Please tak your seat now.

श्री रामेश्वर सिंह : तत्काल वहां पर जा कर व्यवस्था करें। मंत्री लोग भी वहां जाकर देखें। मैं उन को दावत देता हूं आन की। वे वहां आकर उनकी समस्याओं का हल निकालें।

श्री शिवचन्द्र झा (बिहार) : बिहार के कई जिलों की यही हालत है, इस को भी आप नोट कर लें।

(Interruptions)

STATEMENT BY MINISTER— PAYMENT OF BONUS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (Dr. RAM KRIPAL SINHA) : Sir, with your permission I have to make the following statement.

The demand for restoration of the minimum bonus which workers enjoyed be- ore the Emergency came up as a natural consequence of the demand to right the wrongs of the Emergency, and it was decided in August last year to restore the minimum bonus of 8·33 per cent for the accounting year 1976 subject to the provisions of the Payment of Bonus Act which empowered Government to protect marginal and sick units. Since then requests have been received from various quarters for amendment of the Payment of Bonus Act, 1965 in certain respects. These include restoration of the original provisions of Section 34, deletion altogether of Section 34 making the 1977 amendment a permanent feature of the Act, extension of the Act to new areas and changes in the formula for computation of bonus. Some proposals have also been made to consider conversion of a part of the bonus or the whole of retirement benefits, unemployment benefits, and the like. It is the intention of the Government to study these proposals closely and to have consultations with the interests concerned before introducing permanent changes in the Act. Meanwhile, in view of the onset of the festival season it has been decided that the *status quo* should be maintained for one more year. Accordingly steps are being taken to continue the pattern of bonus payment prescribed in the Amendment Act of 1977, namely, 8·33 per cent minimum bonus regardless of profit, to be paid for the accounting year commencing on any day in the year 1977.